आपसे सिर्फ वहीं लोग जलेंगे जिन्होंने आपकी सफलता देखी है, संघर्ष नहीं।
– अज्ञात

सरकार तीनों नियुक्तियां जल्द करेगी

कारण यह कि इसमें रिजर्व बैंक इकॉनमी में नकदी का फ्लो सुनिश्चित करने और मुद्रा स्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख ब्याज दरें तय करता है, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति का वस्तुगत आकलन भी पेश करता है, जिसके आधार पर निवेशक अपना रुझान तय करते हैं।

सिदार्थ साहनी।।

रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) की हर दूसरे महीने होने वाली बैठक इस बार नहीं हो सकी। यह कोई मामूली सूचना नहीं है। मंगलवार यानी 29 सितंबर से शुरू होकर इसे 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन सोमवार को ही रिजर्व बैंक की तरफ से बैठक स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी गई।

आधिकारिक तौर पर न तो इसकी कोई वजह बताई गई है, न ही यह सूचना दी गई है कि बैठक कब तक के लिए टाली गई है। माना जा रहा है कि बैठक टलने का कारण इस कमिटी के बाहरी सदस्यों की समय पर नियुक्ति न हो पाना है। एमपीसी में छह सदस्य होते हैं जिनमें तीन आरबीआई के अंदर के होते हैं और तीन इससे बाहर के। अंदर के सदस्यों में गवर्नर, डेप्युटी गवर्नर और एग्जिक्युटिव डायरेक्टर (मॉनिटरी पॉलिसी) होते हैं।

आरबीआई से बाहर के तीनों सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इनका कार्यकाल चार साल का होता है। एमपीसी की व्यवस्था अक्टूबर 2016 से शुरू हुई तो इन तीनों सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगस्त में हुई एमपीसी की पिछली बैठक के बाद तीनों इस कमिटी से हट गए। इसके बाद स्वाभाविक तौर पर अपेक्षा की जा रही थी कि सरकार इनकी जगह तीन नए सदस्यों को मनोनीत कर देगी, लेकिन उसकी तरफ से अबतक ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकी है। नतीजा यह कि देश की मौद्रिक नीति तय करने वाली इस कमिटी की बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी और यह भी नहीं पता कि आगे कब होगी। ध्यान रहे, एमपीसी की बैठक बैंकिंग व्यवस्था के ही लिए नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। कारण यह कि इसमें रिजर्व बैंक इकॉनमी में नकदी का फ्लो सुनिश्चित करने और मुद्रा स्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख ब्याज दरें तय करता है, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति का वस्तुगत आकलन भी पेश करता है, जिसके आधार पर निवेशक अपना रुझान तय करते हैं।

कोरोना और लॉकडाउन से उपजी चुनौतियों को ध्यान में रखें तो एमपीसी की इस बार वाली बैठक कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रिजर्व बैंक ने कर्जों की ईएमआई टालने जैसी कुछ रियायतें भी घोषित कर रखी हैं। इनके प्रभावों का सटीक आकलन होना जरूरी है, ताकि बैंकों द्वारा इन्हें बंद करने या आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सके। साफ है कि एमपीसी की बैठक न हो पाना एक ऐसी अनिश्चितता को जन्म दे रहा है, जो किसी आर्थिक तर्क से नहीं उपजी। यह सरकारी लापरवाही से या किसी विचित्र तर्क के झोंके में अर्थव्यवस्था पर बाहर से लादी गई है। वैसे भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में ढिलाई का संदेश जाना किसी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता।

एनडीए–1 के दौरान लोकपाल की नियुक्ति में हुई करीब पांच साल की देरी पर आज भी सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तीनों नियुक्तियां जल्द करेगी और एमपीसी की बैठक को लेकर बनी अनिश्चितता ज्यादा लंबी नहीं खिंचेगी।

अच्छा काम

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

सुबह के समय जल्दी उठकर पुरी सुबह को ही अपने कब्जे में कर ले, ताकि आप अच्छे से अच्छा काम कर सको। स्वस्थ नाश्ता करना हो या किताब न्यूज पढ़ना हो या फिर आपके सबसे ज्यादा चतपवतपजल के काम खत्म करना हो, सुबह सुबह यह काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाते है। दिमाग और उत्साह से किये हुए काम का तमेनसज भी कई गुना अच्छा आता है। जब दुनिया में बाकी लोग पलंग पर आराम कर रहे होते है तभी आपको अपने ये सारे काम कर लेने चाहिये। और सुबह को अपने कब्जे में कर लेना चाहिये।
अपने दिन की शुरुवात एक स्पष्ट उद्देश के साथ शुरू करने से आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो।

संपादकीय

सियाचिन जैसी तैनाती

भारतीय सैन्य हलकों में यही बड़ी चिंता है कि पूर्वी लद्दाख की पर्वतीय चोटियां, पैंगोंग झील, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग के मैदानी इलाके अभी सियाचिन ग्लेशियर जैसी सैन्य तैनाती की शक्ल लेने लगे हैं। साथ में दोनों यह संदेश भी देना चाहते हैं कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे का मनोबल गिराने के लिए शक्ति प्रदर्शन के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव एक दूसरे पर डाल रहे हैं। चीनी दैनिक 'ग्लोबल टाइम्स' कह रहा है कि लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर शून्य से चालीस डिग्री नीचे तापमान में भारतीय सैनिक गल कर वहां दफन हो जाएंगे जबकि भारतीय सैन्य अधिकारी कहने लगे हैं कि अपने सियाचिन अनुभवों का फायदा उठाते हुए हमारे सैनिक पूर्वी लद्दाख के सीमांत बर्फीले इलाकों में चीनी सैनिकों के पसीने छुड़ा देंगे क्योंकि चीनी सेना का इतने ठंडे इलाके में लंबे वक्त तक के लिए तैनात रहने का कोई अनुभव नहीं है। चीन अपनी इस मंशा को पूरा करने में कामयाब हो रहा है कि उसकी शर्तें नहीं मानने पर भारत को अपने इलाके की चौकसी के लिए विपरीत परिस्थितियों में करीब 50 हजार सैनिकों को तैनात करने का फैसला करना पड़ा है और इस पर होने वाले रोजाना करीब सौ से 150 करोड रुपये के खर्च का भारी बोझ ऐसे वक्त उठाना पड़ेगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी की चोट से कराह रही है। चीन की कथनी और करनी में अब तक हम भारी फर्क देखते आए हैं।

भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ें नहीं, इसकी चिंता दोनों सरकारों को है। संभवतः इसी उद्देश्य से सैन्य कमांडरों की बैठक में पहली बार साझा बयान जारी किया गया है।

नवंबर में शिखर बैठक

रंजीत कुमार।।

करीब पांच महीनों से चल रही सैन्य तनातनी को दूर करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बीते 21 सितंबर को हुई छठे दौर की वार्ता में चीन ने फिर अपना अड़ियल रुख दिखाया। परिणाम यह कि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और अब यही लग रहा है कि पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर दोनों देशों की सैन्य तैनाती अगले कुछ बर्फीले महीनों तक या इससे भी आगे बनी रहेगी। भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ें नहीं, इसकी चिंता दोनों सरकारों को है। संभवतः इसी उद्देश्य से सैन्य कमांडरों की बैठक में पहली बार साझा बयान जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युद्ध कब तक टलेगा। सीधी खुली लड़ाई से बचने के लिए दोनों में से एक पक्ष को तो झुकना ही पड़ेगा।

दोनों पक्षों के कड़े रुख को देखते हुए राजनयिक पर्यवेक्षकों की निगाह अब नवंबर के शुरू में रूस में होने वाली शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक पर होगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिन फिंग आमने–सामने हो सकते हैं। जैसे रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक एससीओ के ही आयोजनों में शारीरिक मौजूदगी में हुई, उसी

तरह यदि शिखर बैठक भी इन नेताओं की शारीरिक मौजूदगी में होती है तो रूस में नरेंद्र मोदी और शी चिन फिंग की मुलाकात हो सकती है। सवाल यह उठता है कि चीन के जिस नेता की विस्तारवादी समरनीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूर्वी लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर, ताइवान और हांगकांग के अलावा दक्षिण एशिया और अफ्रीका तक पांव पसारने की रणनीति को अमल में लाया जा रहा है, वह अपने कदम पीछे हटा कर भारत के समक्ष झुकने का संदेश दुनिया को कैसे दे।

चीन कहता है कि तनाव दूर करने का दारोमदार भारत पर है और वह तनाव दूर करने के लिए बीच का रास्ता अपनाए जबकि भारत कहता है, चीन पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर पांच मई से पहले की यथास्थिति बहाल करे। भारत और चीन की शिखर मुलाकातें ही अब रिश्तों की दिशा तय करेंगी और इन्हीं वार्ताओं पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच सीमांत इलाकों में सैन्य तनातनी क्या आकार लेती है। अंतिम उम्मीद शीर्ष राजनीतिक गुफ्तगू पर ही है, अन्यथा मसले को सुलझाने के लिए युद्ध ही विकल्प बचता है। इसी इरादे से आला राजनीतिक बैठकों के पहले दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के सातवें दौर की बैठक और इसके पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के राजनयिकों की अध्यक्षता वाली वर्किंग मेकनिज्म फॉर कन्सल्टेशन एंड को–ऑर्डिनेशन (डब्ल्यूएमसीसी) की बैठकों का दौर चलाने का फैसला किया गया है।

मास्को में चार सितंबर को भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों और फिर दस सितंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकातों का कोई ठोस नतीजा नहीं सामने आया। इन दोनों उच्चस्तरीय वार्ताओं की पृष्ठभूमि में बीते 21 सितंबर को भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की छठे दौर की बैठक के बारे में यह कहा जाए कि दोनों देशों ने युद्ध टालने पर सहमति का साझा बयान जारी किया तो गलत नहीं होगा। छठे दौर की वार्ता में जमीनी स्थिति नहीं बदलने और नई सैनिक तैनाती नहीं करने पर सहमति का यही मतलब है कि चीनी सेना जिन इलाकों में जहां तक आगे बढ़ चुकी है उसी को वह नई वास्तविक नियंत्रण रेखा बनाने पर तुली है, जहां से शांतिपूर्वक उसे पीछे नहीं हटाया जा सकता।

सूडोकु नवताल- 5492

कठिन

	8			6				
					5			
		9				7		3
	1			8				2
			7		4			
6				3			8	
5		7				4		
			8					
				1			6	

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5491 का हल

9	4	5	3	1	8	7	6	2
1	8	6	7	2	5	4	9	3
2	7	3	9	4	6	8	1	5
6	3	9	1	7	4	2	5	8
5	2	4	8	9	3	6	7	1
7	1	8	6	5	2	9	3	4
4	6	7	5	8	1	3	2	9
8	9	1	2	3	7	5	4	6
3	5	2	4	6	9	1	8	7

अपना ब्लॉग

हाथी और ड्रैगन का साझा नृत्य

मोहन। वैसे तो भारत में चीन के राजदूत और चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों में दो हजार सालों की दोस्ती, हाथी और ड्रैगन का साझा नृत्य और विवादों को झगड़े में नहीं बदलने जैसी बातों पर जोर दिया जाता है लेकिन चीन यह अपनी ही शर्तों पर चाहता है। इसलिए इस बार भी साझा बयान में जो आपसी सहमति व्यक्त की गई है, उसको इसी नजरिये से देखा जा सकता है कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में जिन चोटियों पर भारतीय सेना ने कब्जा किया उससे चीन की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो गई, इसलिए उसने साझा बयान में भारत से यह सहमति ली है कि अग्रिम मोर्चों पर अब और सैन्य तैनाती न की जाए। चूंकि दोनों देश नहीं चाहते कि किसी तरह की सैन्य झड़प या खुला युद्ध हो इसलिए दोनों की कोशिश है कि वहां अपनी सैन्य ताकत दिखा कर एक–दूसरे को झुकने या पीछे हटने को मजबूर किया जाए।